Visit of an Industrial Delegation from Japan

6917. SHRI B. V. DESAI:
SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a top level delegation of 10 large industrial groups from Japan visited India for holding a discussion with the Central and State Governments;

(b) if so, whether any agreement has been reached between the two countries;

(c) if so, in what field; and

(d) the main feature of the agreement arrived at?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) to (d). No, Sir. No discussions were held with State and Central Governments by top Japanese industrialists. However, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has reported that the 13th Joint Meeting of the Business Cooperation Committee of Indian and Japan was held in New Delhi on the 9th December, 1980. This Committee aims at fostering friendship and understanding between the business communities of Japan and India and at promoting trade and economic cooperation between the two countries. The Committee noted that the development programmes in India offer enlarged opportunities for transfer of Japanese technology and investment on a much larger scale to mutual benefit. The scope for participation in third country projects by the organisations in the two countries was also recognised.

गुजरात में बसाये गये आदिवासियों बंधुआ मजदूर

6918. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिवासी बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के अन्तर्गत गुजरात में बसाये गये आदिवासी बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है;

(ख) आदिवासी बंधुआ मजदूरों को किस प्रकार की राहत दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुजरात में आदिवासी बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में 20 आदिवासी बंधुआ श्रमिक थे, जिनको उनके भूतपूर्व नियोजक द्वारा 21 गुन्था भूमि दी गई और उन्हें प्राथमिकता आधार पर समाज कल्याण निदेशालय की विशिष्ट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत लाभ दिए गए । केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत उनको सहायता देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है । बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के सम्बन्ध में पूरी छानबीन करने के लिए राज्य के बजट में 50,000 रुपये की व्यवस्था की गई है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

6919. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1978 से 1980 तक वर्षवार प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये और उसमें से अनुसूचित